इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सड़क 2019 तक पूरी होगी : मंत्री

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

निर्माण की समीक्षा

- पैसा देने के बावजूद जमीन अधिग्रहण की धीमी गित पर चिंता व्यक्त की
- 679 किमी सड़क के निर्माण से राज्य के सात जिलो को होगा लाभ

पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव ने कहा है कि इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बिहार के हिस्से में पथ निर्माण का कार्य 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1655 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने जमीन के लिए 2242 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने पैसे की व्यवस्था करने के बावजूद अब तक मात्र 60 प्रतिशत जमीन की ही व्यवस्था होने पर चिन्ता प्रकट की। साथ ही इसे तेज करने का निर्देश दिया।

श्री यादव गुरुवार को भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सात जिलों से होकर गुजरने वाली 679 किलोमीटर की इस सड़क के निर्माण का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार के जिम्मे है। 552 किमी सड़क राज्य उच्च पथ है जिसका निर्माण टू-लेन में किया जा रहा है। शेष 127 किमी राष्ट्रीय उच्च पथ है। इसके भी चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। बिहार-यूपी सीमा से सटे पश्चिम चम्पारण के मदनपुर से शुरू होकर यह सड़क किशनगंज के गलगलिया में बंगाल बॉर्डर के पास समाप्त होगी। इस सीमा सड़क से पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों को लाभ होगा।

श्री यादव ने बताया कि बैठक में भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के एलाइनमेंट (आरेखन) में राज्य योजना (नाबार्ड) के अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 121 लघु एवं वृहद् पुलों के निर्माण की समीक्षा की गई। इस क्रम में पुल निर्माण निगम और पथ निर्माण विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों को पथ का संयुक्त निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि कोई भी निर्मित पुल बिना पहुंच पथ का नहीं रहे।